बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 73

प्रतिष्ठा को क्षति

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों को इतिहास इसलिए याद रखेगा क्योंकि इन चुनावों में प्रचार अभियान के दौरान तमाम विचारधाराओं के राजनेताओं ने शिष्टाचार को ताक पर रख दिया और उनमें पश्चाताप की कोई भावना भी नहीं नजर आई।

इसकी जवाबदेही एक हद तक निर्वाचन आयोग पर भी आयद होती है। आयोग की निष्पक्ष छवि इन चुनावों में काफी हद तक भंग हुई है। यह चिंता की बात है कि अपने निष्पक्ष चरित्र के लिए जाना जाने वाला यह संस्थान जिसे सन 1990 के दशक में टीएन शेषन के बाद तमाम निर्वाचन आयुक्तों ने एक के बाद एक बहुत सावधानीपूर्वक खड़ा किया। परंतु अब इस निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं मेनका गांधी, योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कार्रवाई की। आयोग ने गांधी, आदित्यनाथ और अन्य पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया लेकिन यह प्रतिक्रिया अपर्याप्त साबित हुई।

यह सच है कि निर्वाचन आयोग के पास अनुशासन भंग करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के सीमित अधिकार हैं लेकिन दुख की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को उसे उसके अधिकारों की याद दिलानी पड़ी। अगर उसने अपने अधिकारों का तत्परता से और पूरी तरह इस्तेमाल किया होता तो निर्वाचन आयोग राजनेताओं को कहीं अधिक सख्त संदेश दे सकता था। वह ऐसा करने में नाकाम रहा और इससे नेताओं को सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ लगातार बढ़ती शिकायतों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निर्देश नहीं दिया।

इसके बाद अचानक उसने जल्दबाजी में तमाम शिकायतों को खारिज कर दिया। इससे उन तीन बंदरों की कथा याद आ गई जो न बुरा देखते थे, न सुनते थे। इसने शाह और मोदी को जिस तरह क्लीन चिट प्रदान की वह अपने आप में प्रमाणों और जमीन पर काम करने वाले चुनाव अधिकारियों को नकारने जैसा था। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की टिप्पणी की, उसे क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान जैसा है। निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने अपना नजरिया पेश करते हुए कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की उस भावना के विरुद्ध है जिसके तहत प्रत्याशी मत पाने के लिए धर्म का सहारा नहीं ले सकते। परंतु बहुमत ने उनकी राय को खारिज कर दिया।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने यह कैसे मान लिया कि मोदी ने बालाकोट और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के लिए वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में भी लवासा चाहते थे कि शिकायतों की प्रतिक्रिया स्वरूप आयोग प्रधानमंत्री से औपचारिक संवाद कायम कर उनसे आचार संहिता का पालन करने में सहयोग करने को कहे। आयोग ने बहुमत से इसकी भी अनदेखी करते हुए क्लीन चिट दे दी। जिस प्रकार लवासा की तार्किक राय की अनदेखी की गई, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि आयोग अपनी प्रतिष्ठापूर्ण राह से विचलित हुआ है। लवासा का विचार था कि इन शिकायतों पर आयोग के आदेशों को सार्वजनिक किया जाए और यह जाहिर किया जाए कि उनकी राय बहुमत से अलग थी। जरूरी नहीं कि आयोग के इस आचरण का असर चुनाव नतीजों पर पड़े लेकिन इससे उसकी प्रतिष्ठा को अवश्य क्षति पहुंची है।

विनय सिन्हा

नरेंद्र मोदी की नई 'मंदिर' परियोजना

मोदी ने वाराणसी के तंग और गंदगी भरे पुराने शहर को नए सिरे से विकसित करने की शुरुआत की है। यह एक ऐसी परियोजना है जो उनके व्यापक हिंदू समर्थकों को प्रसन्न कर सकती है।

चुनाव की बात

शेखर गुप्ता

बीते 15 वर्ष के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों की चुनावी यात्राओं के दौरान मैंने 'दीवार पर लिखी इबारत' रूपक को सही पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में चुनावों के दौरान त्योहारों से भी अधिक उत्सव का माहौल रहता है। इस दौरान लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनकी आकांक्षाएं, उनकी खुशी, उनकी चिंताएं और आशंकाएं आदि सभी दीवारों पर लिखी इबारत से स्पष्ट होती हैं। ये इबारतें भित्तिचित्रों, विज्ञापन, बाड़ों यहां तक कि मलबों से भी प्रकट हो सकती हैं। आप वाराणसी में बदलाव देखना चाहते हैं तो वहां पड़े ताजा मलबे पर से गुजरिए, पास ही एक बुलडोजर नजर आएगा जो काम पर लगा है। दीवारों को केवल देखिए, उन्हें पढ़िए मत क्योंकि वहां पढ़ने को कुछ नहीं है। बस देखिए कि वहां क्या हुआ करता था।

यह दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों, अलमारियों आदि का मलबा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दीवार पर गोंद से चिपकाए गए थे और किसी ने उन्हें वहां से झिंझोड़कर अलग कर दिया है। अगर आपको अचानक आसमान से यहां उतार दिया जाए तो शायद आप सोचें कि आप किसी कलाकृति के बीच खड़े हैं। आपको यह फेवीकोल का विज्ञापन भी लग सकता है जहां बुलडोजर सबकुछ तोड़ देता है लेकिन फेवीकोल का जोड़ नहीं। यहां कमोबेश ऐसा ही हुआ है। केवल 11.4 एकड़ इलाके में करीब 300 घर, मंदिर और अन्य इमारतें खड़ी थीं, जिनमें अधिकांश एक दूसरे से सटी हुई थीं। इनके बीच ही बनारस की चर्चित गलियां थीं। कुछ तो इतनी संकरी कि एक साथ दो लोग भी बमुश्किल ही गुजर पाते। यह सब अब इतिहास हो गया है।

मोदी के आलोचक कहते हैं कि इस इलाके को इसलिए ढहा दिया गया ताकि हिंदुओं के सबसे पवित्र और पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को हिंदू समाज गंगा के घाट से सीधे देख सके। इतना ही नहीं अब लोग इस अपेक्षाकृत छोटे मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद भी आसानी से देख सकेंगे। औरंगजेब ने सन 1669 में मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाकर यह मस्जिद बनवाई थी। यह उग्र हिंदुत्ववादियों की आंख में चुभेगी और अगला निशाना बनेगी। परंतु मेरी नजर में यह कोई खतरा नहीं है। इसलिए नहीं कि काशी विश्वनाथ विकास प्राधिकरण के 36 वर्षीय सीईओ विशाल सिंह तथा अन्य अधिकारी मुझे बताते हैं कि मस्जिद को 30 फुट ऊंचे इस्पात के खंभों से सुरक्षित कर दिया गया है और सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान उसकी सुरक्षा में हैं। मेरा नजरिया यह है कि भले ही मौजूदा दौर में सत्ता बहुसंख्यकवादियों के हाथ में हो और विभिन्न संस्थान इतने कमजोर हों कि संविधान की रक्षा न कर पा रहे हों लेकिन एक ऐसी इमारत को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा जो सबके सामने और सबकी पहुंच में हो।

केवल एक इलाके के पुनर्विकास और नदी के घाट से मंदिर और मंदिर से घाट को देखने के लिए 300 मीटर के हिस्से को साफ करने से ऐसा कोई जोखिम नहीं पैदा होता। कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से ऐसी आशंका जताती हुई याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी जो खारिज कर दी गई। इसका बड़ा विरोध वाराणसी के हिंदू रूढ़िवादियों ने किया। मंदिर के नीलकंठ गेट से पवित्र मणिकर्णिका घाट की ओर जाने वाली गली से गुजरते हुए मेरी मुलाकात सुप्रसिद्ध स्थानीय लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी त्रिलोचन प्रसाद से हुई। वह बेहद खफा हैं। जो चीजें कभी नहीं बदलनी थीं उन्हें बदलने का दुस्साहस कौन कर सकता है? उन्होंने हमारी विरासत को नष्ट किया है। हर पवित्र चीज को नष्ट किया है। सैकड़ों करोड़ रुपये बरबाद किए गए, इसके साथ ही एक पूरी जीवन शैली और तमाम अन्य चीजें नष्ट कर दी गईं। आप मोदी को पसंद करें या नहीं लेकिन वह जोखिम उठाते हैं। 4.6 हेक्टेयर के इस इलाके का पुनर्विकास, जिसमें 296 इमारतें गिराई गईं, उनके द्वारा लिया गया एक बड़ा जोखिम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे केवल उदारवादी ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों के गढ़ के रूढ़िवादी नागरिक भी नाराज हुए। ये वे लोग हैं जो बदलाव को सही नहीं मानते। इस क्षेत्र से जिन लोगों को हटाया गया उनमें 90 फीसदी ब्राह्मण हैं। अपने पुजारियों की तरह वाराणसी में राजनीतिक पंडितों की भी कमी नहीं। उनमें से कई पूरे यकीन से आपको बताएंगे कि मोदी और योगी का यह दुस्साहस उन्हें 60 से 75 हजार वोट का नुकसान पहुंचाएगा।

यह क्षेत्र कैसा था और अब कैसा है, यह समझने के लिए सीईओ कार्यालय में लगे चार्ट और प्लास्टिक मॉडल देखने होंगे। सीईओ खुद मैरीलैंड विश्वविद्यालय से एमबीए हैं। प्राधिकरण को 600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और कानून बनाकर पुरानी इमारतों का अधिग्रहण किया गया। घरों के मालिकों को सर्किल रेट से दोगुनी दर पर भुगतान किया गया और वे कमोबेश प्रसन्न नजर आए। उन्हें कुल 200 करोड़ रुपये की राशि चुकाई गई। 15 करोड़ रुपये की राशि उन लोगों को दी गई जिनके पास मालिकाना हक नहीं था लेकिन किरायानामा था। मंदिर के आसपास केवल 12 लोग ऐसे हैं जो अब भी काबिज हैं।

तोड़फोड़ काम पूरा हो चुका है। मोदी ने 8 मार्च को नए परिसर का भूमि पूजन किया और एक साल में काम भी पूरा हो जाएगा। अब तक 43 मंदिरों का पता चला है जो घरों के भीतर छिप गए थे। यह ज्यादातर अतिक्रमण का मामला था। काम पूरा होने के बाद यह परिसर साफ सुथरा, आधुनिक और पहुंच लायक हो जाएगा। यानी यह उस तरह का हो जाएगा जिसका दावा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी पुराना वाराणसी शहर पांच साल में नहीं कर सका। क्या यह जोखिम उठाने लायक था?

शहरों के अंदरूनी हिस्सों का विकास बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे अधिकांश नेता इससे दूर ही रहते हैं। ऐसा पहला प्रयास संजय गांधी ने तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद इलाके में किया था। परंतु वह एक तानाशाही प्रकृति के व्यक्ति थे जो किसी से कुछ नहीं पूछते थे। ऐसे दूसरे व्यक्ति एक आधात्मिक गुरु हैं जिनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना, मध्य मुंबई के भिंडी बाजार में 4,000 करोड़ रुपये का पुनर्विकास कार्य करा रहे हैं। मोदी ऐसे तीसरे व्यक्ति हैं लेकिन कानून की मदद से और धनराशि वितरित करके ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति भी हैं।

हम धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं और सबका साथ, सबका विकास नारे के खोखलेपन को भी उजागर करते हैं लेकिन हमें यह मानना होगा कि उन्होंने हिंदुत्व की सामाजिक रूढ़िवादिता को चुनौती भी दी है। स्वच्छ भारत और खुले में शौच से मुक्ति का अभियान इसके दो पहलू हैं। एक अन्य बात जिसे भुला दिया गया वह है गुजरात में सार्वजनिक स्थान का अतिक्रमण कर रहे मंदिरों को हटाया जाना। इसके चलते उन्हें विश्व हिंदू परिषद का दुश्मन बनना पड़ा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर वह वाराणसी के रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद से पंगा ले रहे हैं। कई ज्ञानी और प्रसिद्ध व्यक्तियों ने वाराणसी के बारे में यादगार बातें कही हैं। उनमें सबसे अधिक शायद मार्क ट्वेन को उद्धृत किया गया है जिन्होंने कहा था, 'बनारस इतिहास से भी पुराना, परंपराओं से भी पुराना और यहां तक कि किवदंतियों से भी पुराना है। अगर इन सबको मिला भी दिया जाए तो भी यह इन सबसे करीब दोगुना पुराना है।' प्रश्न यह है कि क्या इसे उतना ही गंदा और उलझाऊ बना रहने दिया जाए? यकीनन हिंदुत्व को अपने पवित्रतम और सबसे पुराने शहर के लिए बेहतर हालात की आवश्यकता है। ट्वेन मंदिर की दीवारों के इर्दगिर्द उभरे नए खालीपन से चकित रह जाते। यह बदलाव की जुबान है।

कुछ ही लोगों को संशय होगा कि मोदी वाराणसी से दोबारा जीतेंगे या नहीं। 23 मई को हमें यह भी अंदाजा लग जाएगा कि मोदी ने उन हजारों पंडितों के वोट गंवाए या नहीं। अगर वह एक वर्ष में परियोजना पूरी कर लेते हैं तो यह उनके देश भर के हिंदू समर्थकों के बीच बड़ी करामात हो सकती है। मैं यह कहते हुए प्रसन्न हूं कि मुझे इस परियोजना ने उत्साहित किया है। यह अन्य पुराने शहरों के सामने बहुत बड़ी नजीर होगी। आशा की जा सकती है कि इस तर्ज पर पुरानी दिल्ली के पैदल चलने वालों के लिए यह परियोजना उस क्षेत्र की पुरानी शान बहाल कर सकती है। अगर मोदी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में इसी तरह प्रगति करते रहे तो बेहतर होगा कि उनकी छवि मध्यकालीन मस्जिदों को ढहाने के बजाय प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके मजबूत हो।

चुनाव नतीजों को लेकर अटकलों और संभावनाओं पर एक नजर

नीति नियम

मिहिर शर्मा

पिछले कई महीनों से तमाम लोग एक-दूसरे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। यह सवाल ऐसा है जो किसी अभिवादन या बातचीत शुरू करने का जरिया बन सकता है। असल में, इस सवाल को पूरा पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप यह भी पूछ सकते हैं कि 'कितनी आ रही हैं?'

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कितनी सीटें जीतेगी? इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं जानता है और न तो इसके आसपास भी पहुंच सकता है। केवल मतदान सर्वे करने वाले ही कुछ बता सकते हैं लेकिन अब तक के एग्जिट पोल नतीजों को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन उनके दिमाग में एक संख्या होने की संभावना है। लेकिन इस संख्या पर ही निर्भर करेगा कि अगले पांच वर्ष कैसे दिखेंगे? ऐसे में हम भाजपा की सीटों से जुड़े परिदृश्य पर गौर करते हैं।

272 प्लस: भाजपा के अकेले दम पर बहुमत हासिल करने का मतलब है कि उसने फिर से हिंदीभाषी राज्यों में विरोधियों का लगभग सफाया कर दिया है और वह बाकी हिस्सों में भी सफल रही है। इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास मुकाम मिल जाएगा। उनके पास अपने पहले कार्यकाल की तुलना में अपने एजेंडा पर आगे बढ़ने के लिए अधिक समर्थन होगा। मोदी को पहले की ही तरह अपने सहयोगी दलों या अपने दल के भीतर भी किसी से सलाह की जरूरत नहीं होगी। अब उन्हें बखूबी पता चल चुका होगा कि नया कार्यकाल 'विकास' की चर्चा से कम, राष्ट्रवादी एवं ध्रुवीकरण विमर्श से अधिक मिला है। इससे उन्हें अपना एजेंडा तय करने में मदद मिलेगी।

230-272: अगर भाजपा बहुमत के आंकड़े से दो दर्जन सीटें दूर रह जाती है तो भी उसे मोदी की ही जीत माना जाएगा। उन्होंने वर्ष 2014 में पश्चिमी एवं उत्तरी भारत के छह बड़े राज्यों की 194 सीटों में से 90 फीसदी पर भाजपा को जीत दिलाई थी। ऐसे में इस बार 230-272 सीटें आने को मोदी की लोकप्रियता में आंशिक गिरावट माना जाएगा। ये इलाके काफी हद तक मोदी के प्रति निष्ठावान बने हुए हैं लेकिन दक्षिण एवं पूर्वी भारत में भाजपा को अधिक कामयाबी नहीं मिली होगी। सत्तारूढ़ गठबंधन में मोदी निर्विवाद नेता बने रहेंगे लेकिन मोदी मार्का हिंदुत्व को मानने वाले और दो बार इसे खारिज कर देने वाले इलाकों में विभेद गहराता जाएगा।

210-230: मेरा मानना रहा है कि भाजपा को इस बार करीब 230 सीटें मिलेंगी। यह तर्कसंगत भी है। इसका मतलब होगा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता ने भाजपा को खासी चोट पहुंचाई है और इस राज्य में उसे अपनी आधी सीटें गंवानी पड़ी है। भाजपा को उत्तर एवं पश्चिम भारत के अन्य राज्यों में भी ठीकठाक नुकसान उठाना पड़ा है जो गत वर्ष तीन राज्यों में मिली नजदीकी हार की ही पुनरावृत्ति होगी। मोदी की लोकप्रियता को भाजपा से कहीं अधिक मान लिया जाएगा और मोदी अपना शिकंजा बरकरार रखने के लिए यही दलील देंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में कुछ नए सहयोगी भी जुड़ेंगे। टीआरएस, बीजद और वाईएसआर कांग्रेस के जुड़ने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी अपना सिक्का नहीं चला पाएंगे। सहयोगी दल अपने मतदाताओं को यह जताने की कोशिश करेंगे कि वे सरकार में लगभग बराबरी का दर्जा रखते हैं। केंद्र सरकार के भीतर पीएमओ में हुए सत्ता संकेंद्रण को भी शिथिल करना होगा।

190-210: यह परिदृश्य काफी खतरनाक होगा। अगर भाजपा महज 200 का आंकड़ा पार करती है या उससे नीचे रहती है तो मोदी के लिए प्रभावी जीत का दावा कर पाना मुश्किल होगा। वर्ष 2014 में भाजपा और कांग्रेस के बीच करीब 200 सीटों पर आमने-सामने की टक्कर हुई थी। अगर वर्ष 2019 में भाजपा 200 के आसपास रहती है तो इसका मतलब होगा कि कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली बार सीधी लड़ाई में कांग्रेस को ध्वस्त कर मोदी ने बहुमत हासिल किया था और उसमें उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लगभग सफाये का मुख्य योगदान रहा था। अगर भाजपा 200 तक सिमटती है तो मतलब होगा कि भाजपा दोनों राज्यों में अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई है। फिर भी भाजपा के सबसे बड़े दल होने और पैसों की कोई कमी न होने से मोदी अगर चाहेंगे तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इसके लिए बड़े गठबंधन की जरूरत होगी जिसका हिस्सा उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में शामिल बहुजन समाज पार्टी भी शायद बन सकती है। लेकिन इस बड़े गठबंधन को संभालना और व्यवस्थित रखना मुश्किल होगा और मोदी को अपनी कुछ ताकत गंवानी पड़ेगी।

170-190: मुझे इसकी संभावना नहीं दिख रही है लेकिन 200 से काफी नीचे रहने पर भी भाजपा वाजपेयी-शैली का गठबंधन बनाकर सत्ता का दावा कर सकेगी। मुझे शक है कि उस समय सहयोगी दल मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने की मांग रखेंगे। क्या वह ऐसा होने देंगे? या फिर वह विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? उनकी सोच के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन कांग्रेस शायद सोचती है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो राजग में टूट-फूट होगी और अगले दो साल में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी। उस समय तक मोदी की सशक्त नेता वाली छवि को भी काफी नुकसान हो चुका होगा।

170 से कम: पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था लेकिन अब कुछ लोगों को यह मुमकिन लगता है। इसका मतलब होगा कि राजग चुनाव हार चुका है और कांग्रेस गठबंधन उसके आसपास या आगे निकल चुका है। फिर क्या होगा? क्या 160 सीटें जीतने वाला कांग्रेस गठबंधन सरकार बना पाएगा? शायद नहीं। उस स्थिति में हमें तीसरा मोर्चा दिखाई देगा। लेकिन उसे बाहर से समर्थन कौन देगा- मोदी या राहुल गांधी? मैं तो मोदी पर ही दांव लगाऊंगा कि वह राजीव गांधी की तरह समर्थन देकर सरकार बनवाएं और फिर उसे अस्थिर करें। मोदी इस आस में सरकार गिराएंगे कि स्थिरता के लिए वोट मांगकर वह सत्ता में लौट आएंगे।

कानाफूसी

प्रियंका की सांसत

उत्तर प्रदेश के पशु कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों पशुओं के साथ क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रचार अभियान के दौरान जब प्रियंका गांधी सपेरों के एक गांव से गुजर रही थीं तो उन्होंने अचानक वहां रुकने की इच्छा जताई। इतना ही नहीं, वहां उन्हें कई पेशेवर सपेरे नजर आए तो उन्होंने उनकी टोकरी खुलवाकर एक नाग निकाल लिया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। यह मामला जब जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने अतिरिक्त जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक जांच गठित कर दी। जांच समिति से कहा गया कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस जांच में सपेरे द्वारा सांप को पकड़े जाने की परिस्थितियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही इस बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आपका पक्ष

देश में विज्ञान पर्यटन को बढ़ावे की पहल

बिहार सरकार ने पटना से सटे तारेगना (मसौढ़ी) खगौल एवं तारेगना टॉप (बिहटा) को एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट, सरल भाषा में कहें तो विज्ञान पर्यटन के एक गलियारे के तौर पर विकसित करने के लिए पहल शुरू कर दी है। सरकार के इस कदम से लगता है कि आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक की कर्मस्थली के दिन बहुरने वाले हैं। यदि पहल जमीन पर उतरती है तो निस्संदेह यह देश में विज्ञान पर्यटन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। साथ ही यह परियोजना देश के इस पिछड़े प्रदेश की आर्थिक सेहत भी दुरुस्त करने में मददगार साबित होगी। यह बात अपने आप में अचंभित करती है कि जिस आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र (तब कुसुमपुर) में 476 ईस्वी में हुआ था, उनके नाम और काम को पहचान दिलाने के लिए आजादी के इतने दशक बाद बीत जाने के बाद भी सरकार के स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। यह कहीं न कहीं विज्ञान के प्रति सरकारी उदासीनता का ही एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अब भी यदि इस निर्णय को मूर्त रूप दिया जाता है तो यह न केवल सच्चे अर्थ में उस महान वैज्ञानिक के प्रति श्रद्धांजलि होगी बल्कि देश में विज्ञान के छात्रों को प्रेरणा देने वाला एक बड़ा प्रेरणा स्थल साबित होगा। इस परियोजना के तहत, आर्यभट्ट की कर्मस्थली को उनके ऐतिहासिक तथा खगोलीय महत्त्व के अनुसार विकसित किया जाएगा। इन जगहों पर थीम के आधार पर एस्ट्रोनॉमी सेंटर, संग्रहालय एवं वेधशाला की स्थापना का प्रस्ताव है। वेधशाला में टेलीस्कोप सहित अनेक उपकरण होंगे। तारेगना (मसौढ़ी) तारेगना टॉप (बिहटा) और खगौल करीब 30-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तीनों स्थानों को मिलाकर एक खास खगोलीय त्रिकोण बनता है, जो तारों और ग्रहों की सटीक गणना में काफी मददगार होता है। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं कि तारेगना में आर्यभट्ट की वेधशाला थी जहां से वह शोध करते थे। ऐसे में यहां पर एस्ट्रो टूरिज्म सेंटर स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। तारेगना के खगोलीय महत्त्व को देखते हुए नासा सहित कई संस्थाएं अंतरिक्ष जगत के रहस्यों के अध्ययन के लिए यहां आती रही हैं।

सुजीत कुमार, पटना

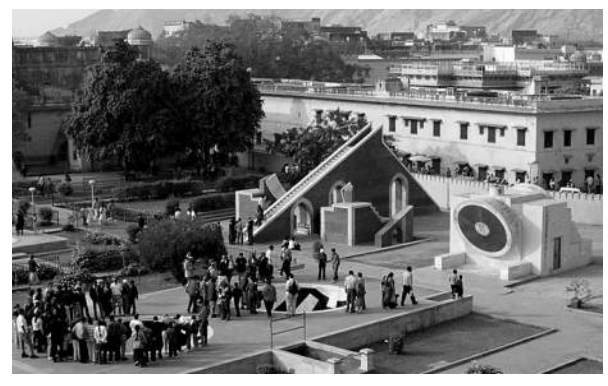

वैज्ञानिक शोध से जुड़े आयोजनों पर जंतर-मंतर पर जुटते हैं वैज्ञानिक रुचि वाले सैलानी

घड़ियाली आंसू नहीं, हो ठोस कार्रवाई

राजस्थान के अलवर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यह घटना अप्रैल के अंतिम हफ्ते में घटी थी लेकिन थाने में प्राथमिकी कई हफ्ते बाद दर्ज की गई जिसे लेकर देश की सियासत उफान पर है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस मामले में राजनीतिक दलों की ओर से जो अति सक्रियता नजर आ रही है उसमें कहीं न कहीं मौजूदा लोकसभा चुनाव भी एक वजह है। इस तरह के घृणित कृत्य के बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष की ओर से हर बार रटी रटाई बातें सामने आती हैं जबकि निर्भय कांड के बाद लगा था कि अब समाज, प्रशासन और बच्चों के माता पिता संवेदनशील बनेंगे। लेकिन लगता है कि राजनीति हावी होने के चलते ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और शीघ्र न्याय पाने की बात फिलहाल दूर की कौड़ी है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।